भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4429

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"ईवी चार्जिंग स्टेशनों का कार्यकरण"

4429. श्रीमती चिंता अनुराधा:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्यशील ईवी चार्जिंग स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा बया है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) निजी और सरकारी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ग) सभी राज्यों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के असमान वितरण के क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ईवी चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, 23.03.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की कुल संख्या 6586 है। देश में प्रचालनरत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पास उपलब्ध डेटा के मुताबिक़, 23.03.2023 की स्थिति के अनुसार देश में 3199 निजी और 3,387 सरकारी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन प्रचालनरत हैं।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना पर इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम,2003 के उपबंधों के संदर्भ में 13.04.2018 को स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों की चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम,2003 के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(घ) से (ङ) : फेम-इंडिया स्कीम के चरण-।। के अंतर्गत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं। साथ ही,फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर भी 1576 चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपेक्षित चार्जिंग अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार ने निम्नांकित पहलें भी की हैं-

(i) विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर एक अधिसूचना जारी कर आवासों और कार्यालयों में निजी चार्जिंग की अनुमति दी है।

(ii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग बाइलॉज,2016 में संशोधन किया है ताकि निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और अवसंरचना की स्थापना हो सके।

***

अनुलग्नक

राज्यवार प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रचालनरत पीसीएस की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	3
2	आंध्र प्रदेश	222
3	अरुणाचल प्रदेश	9
4	असम	48
5	बिहार	83
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ	46
8	दिल्ली	1,845
9	गोवा	44
10	गुजरात	195
11	हरियाणा	232
12	हिमाचल प्रदेश	27
13	जम्मू और कश्मीर	24
14	झारखंड	60
15	कर्नाटक	704
16	केरल	192
17	लक्षद्वीप	1
18	मध्य प्रदेश	174
19	महाराष्ट्र	660
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	19
22	नगालैंड	6
23	ओडिशा	117
24	पुदुचेरी	4
25	पंजाब	126
26	राजस्थान	254
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	441
29	तेलंगाना	365
30	त्रिपुरा	18
31	दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
32	उत्तर प्रदेश	406
33	उत्तराखंड	48
34	पश्चिम बंगाल	189
कुल		**6,586**

***